Fourteenth Loksabha

Session : 8
Date : 03-08-2006

Participants : Nishad Shri Mahendra Prasad

an>

Title : Need to declare Non-Governmental District Rural Development Agency employees as Government Servamts.

श्री महेन्द्र प्रसाद निाद (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार का ध्यान आकृट करते हुए कहना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की रोजगार परक योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले देश भर के प्रत्येक जिले में जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों (डी.आर.डी.ए.) में कार्यरत कर्मी/ कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि के मद में भारत सरकार 75 प्रतिशत व प्रदेश सरकार 25 प्रतिशत अंशदान देती है लेकिन कुछ राज्यों को छोड़कर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य सहित कई राज्यों में अभी भी डी.आर.डी.ए. कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता है और न ही सरकारी कर्मचारी की सुविधाएं इन्हें मिलती हैं।

अत: मेरा विचार है कि भारत सरकार द्वारा डी.आर.डी.ए. के कर्मचारियों के ऊपर खर्च, वेतन भत्ता आदि में देय भुगतान की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के गैर सरकारी डी.आर.डी.ए. कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी घोाित करने व कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कट करें।

Shri Anandrao Vithoba Adsul – not present.